



न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र.

निवाशनी 2091-PBR-15

श्री रामचंद्र क शर्मा, कानपुर 1.
द्वारा आज दि. 6-7-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. ईश्वर प्रसाद गोस्वामी पुत्र जानकी वल्लभ गोस्वामी, उम्र 57 वर्ष,
2. राधावल्लभ पुत्र धनसुन्दर, उम्र 66
3. रमेश कुमार पुत्र वैजनाथ, उम्र 45 साल
4. श्रीवल्लभ फौत द्वारा वैध वारिसान हारिओम व विनोद पुत्रगण श्रीवल्लभ उम्र क्रमशः, 32 व 30,
5. प्रभात पुत्र दुर्गा प्रसाद, उम्र 48 साल
6. बालकृष्ण पुत्र नन्नु लाल, उम्र 50
7. भावती प्रसाद फौत द्वारा वारिस रामेश्वर प्रसाद पुत्र भावती प्रसाद उम्र 40 वर्ष
8. वीरेन्द्र कुमार पुत्र राधा वल्लभ उम्र 52 साल
9. दुर्गा प्रसाद पुत्र धनसुन्दर, उम्र 68 साल
10. जानकी वल्लभ पुत्र धन सुन्दर उम्र 75 वर्ष

सम्मत जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम करहौर, तहसील व जिला शिवपुरी हाल टप्पा तहसील सुभापुरा जिला शिवपुरी म.प्र. — आवेदकगण

काम

1. म.प्र. शासन जयकलेक्टर जिला शिवपुरी

— असल आवेदक

मोहन शर्मा (38)

दि 6-2015

मोहन शर्मा

मोहन शर्मा

सिंह
मणा सिंह
मणा सिंह
तित्तू हरिजन
रामकिशन
श्री हरिश्चन्द्र
श्री धोततम
जीवन लाल सोनी
पंचुराम सोनी
भार पुत्र मंगल चन्द

2...

2. अतर सिंह पुत्र मेहताव सिंह
3. गंगा सिंह पुत्र पंचम सिंह
4. सोनी राम पुत्र अतर सिंह
5. स्वरूप पुत्र अतर सिंह
6. बलवंत सिंह पुत्र पंचम सिंह
7. कोकसिंह पुत्र अतर सिंह
8. रामवीर सिंह पुत्र अतर सिंह
9. नरेशा पुत्र सरवंशा सिंह
10. लायक सिंह पुत्र सरवंशा सिंह
11. कदम सिंह पुत्र मंगाराम
12. पन्ना लाल पुत्र करम सिंह
13. लायक सिंह पुत्र लक्ष्मणा सिंह
14. लक्ष्मणा सिंह पुत्र पजन सिंह
15. मेवाराम पुत्र लक्ष्मणा सिंह
16. महेन्दर सिंह पुत्र लक्ष्मणा सिंह
17. मोहर सिंह पुत्र लक्ष्मणा सिंह
- 000 समूह आदिवासी
18. सभायाराम पुत्र उत्तू हरिजन
19. पुरुषोत्तम पुत्र रामकिशन
20. छीतर प्रसाद पुत्र हरिशाचन्द्र
21. राजेशा पुत्र पुरुषोत्तम लोहार
22. हजारी पुत्र जीवन लाल सोनी
23. अशोक पुत्र पंचूराम सोनी
24. सुरेशा कुमार पुत्र मंगल चन्द

Handwritten signature

सोनी

Handwritten signature

300

- 25 सुनील पुत्र हजारी लाल
- 26 मनोज पुत्र रामचरण
- 27 श्री दिमान पुत्र कुंजा ब्राह्मण
- 28 सुखलाल पुत्र हल्लूराम
- 29 ~~अनिल पुत्र रामचरण~~
- 29 रमेश दयाल पुत्र मकखान लाल
- 30 महेंद्र पुत्र नकटू
- 31 वृजेश पुत्र लक्ष्मण
- 32 अशोक कुमार पुत्र दामोदर

सम्मत जाति ब्राह्मण , निवासी ग्राम
करई केरु तहसील व जिला शिवपुरी

-- तरतिवि अनावेदक

निगरानी अर्थात् धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011
एम.पी.एल.आर.सी. विरुद्ध अधिकांश दिनांक 11 जनवरी 93
द्वारा पारित न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी प्र. क्र. 13/92-
93 निगरानी स्वमेव म.प्र. शासन विरुद्ध अतर सिंह आदि के
निष्पत्ति से दुखी होकर

श्रीमान जी,

हम आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, नायब तहसीलदार तहसील व जिला शिवपुरी के
द्वारा भूमि व्यक्तियों को ग्राम करई केरु में दिनांक 11-7-86
को केम्प आयोजित किया गया जिसमें आवेदकगण व अनावेदक क्र. 2

IT
मपि

क

परीत

Handwritten signature

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2091-पीबीआर/15

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.07.2015	<p>आवेदकगण एवं शासन के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। कलेक्टर, जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 11-1-93 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 11-1-93 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 6-7-15 को लगभग 22 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण ग्राम में हुई चर्चा के दौरान आदेश की जानकारी होना दर्शाया है जो कि समाधानकारक नहीं है। जहाँ तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया गया है और न ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की गई है कि 29 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कितने व्यक्ति के अनुसूचित जाति के हैं और कितने व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति के हैं। केवल पटवारी द्वारा आवेदन पत्र भरकर उपसरपंच को प्रस्तुत किया गया है। उपसरपंच द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका पर भूमि बंटन कर दिया गया है, परन्तु न तो पट्टे जारी किये गये हैं और ना ही मौके पर कब्जा दिया गया है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 11-1-86 को निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।</p>	

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

14-7-15